

Inflationary Gap

Inflationary gap की चारणा का प्रतिपादन 1940 में सर्वप्रथम J.M. Keynes ने अपनी पुस्तक 'How to pay for the War' में किया था। Keynes का मत था कि अर्थव्यवस्था अगर पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्यरत है और अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण मौद्रिक मांग बढ़ जाए और उत्पादन पूर्ववत् रहे तो Inflationary gap का जन्म होता है। इस चारणा की निम्न परिभाषा उनी ने

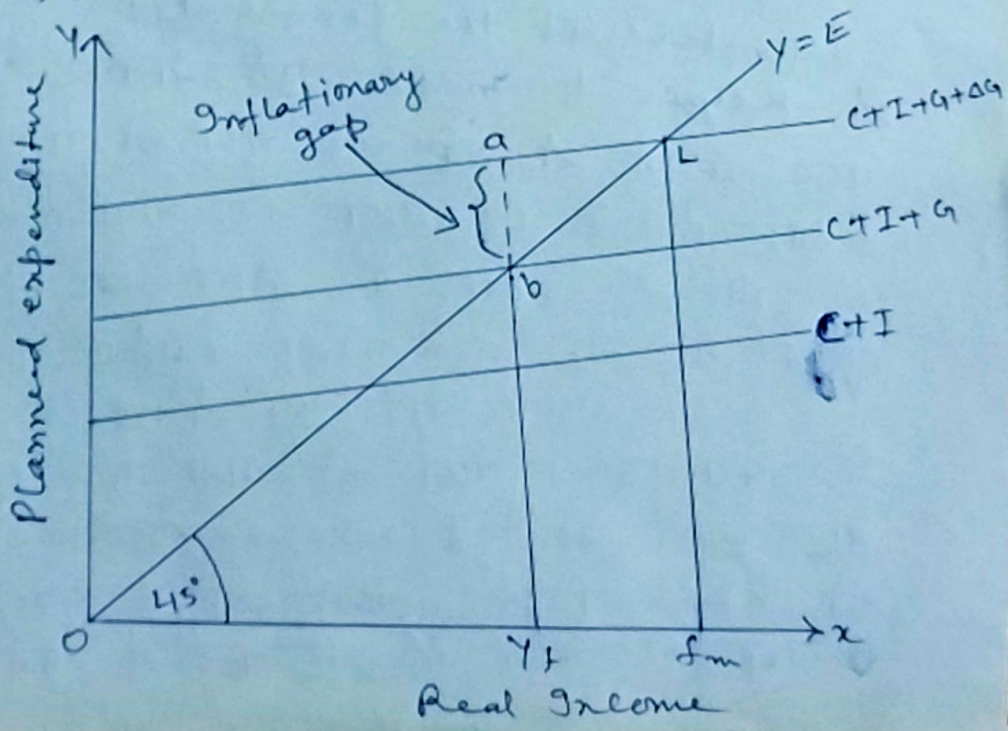
"Inflationary Gap is defined as the amount of the government expenditure against which there is no corresponding increase of real resources of man power or material by some other members of the community."

श्री J.M. Keynes के अनुसार पूर्ण रोजगार के बिंदु पर पहुँचने से पूर्व यदि मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है तो अतः एक अंग रोजगार का विस्तार करेगा और दूसरा अंग उत्पादन-लागत में वृद्धि करके नीचे बढ़ेगा।

परन्तु यदि पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरान्त भी मुद्रा की मात्रा में होना जारी रहती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें गिरती बढ़ती रहती हैं जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है।

इसी कीमत में बत बत अन्तर को
Inflationary gap कहते हैं।

जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तब लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। मौद्रिक आय के बढ़ जाने के फलस्वरूप लोगों का व्यय भी बढ़ जाता है। इससे कीमतों में उपर बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यय योग्य मौद्रिक आय तथा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते हैं तो कीमत-स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में यदि व्यय योग्य मौद्रिक आय अधिक अनुपात में बढ़ती है तो कीमत-स्तर अवश्य ही बढ़ेगा। यही कीमत में अन्तर 'कीमतिक अन्तर' कहलाता है। इसे किन्तु चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं।



उपरोक्त चित्र में वास्तविक आय को Ox तथा
 गिलापित आय को Oy रेखा पर कापा जाता है।
 Y_1 की Ox रेखा आय तथा आय को बीच
 संतुलन को दिखाती है। $C+I$ रेखा पर
 उपभोग तथा विनिर्माण, $C+I+G$ रेखा द्वारा
 उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय और
 $C+I+G+\Delta G$ द्वारा उपभोग, निवेश, सरकारी
 व्यय संव वही हुई सरकारी व्यय को
 व्यक्त करता है। आय को Y_2 स्तर पर
 उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय $(C+I+G)$
 की रेखा P बिंदु पर पूर्ण रोजगार की
 स्थिति में है। अतः आय संव आय संतुलित
 अवस्था में है और G की मात्रा शून्य है।
 अब यदि सरकारी व्यय में ΔG का वरावर
 वृद्धि की जाती है तो संतुलन वगले स्तर
 के लिए वास्तविक आय Y_2 से Y_3 बढ़कर Y_4
 हो जाता है। यहाँ $C+I+G$ तथा $C+I+G+\Delta G$
 रेखा के अन्तर (a) स्थितिक अन्तर का
 शर्तित है।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने *Keynesian*
 गुण की व्याख्या की आलोचना की है -

- ① प्रो. Hansen के अनुसार किन्स ने स्थितिक
 अन्तराल को केवल वस्तु बाजार से संबंधित
 किया है तथा साध्य बाजार की अवहेलना की है।
 जबकि G वस्तु बाजार के साथ ही साध्य

बाजार में आतिरिक्त मांग के कारण उत्पन्न होता है।

② प्रा. रूपरेखा के अनुसार 9.6 static analysis से संबंधित है जबकि inflation की स्थितियों प्रकृति से dynamic होती है।

③ 9.6 इस गल्पता पर आधारित है कि पूर्ण रोजगार स्तर की कीमतों में वृद्धि होती है अर्थात् आतिरिक्त मांग की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जबकि कीमतें बढ़ने से लागत की मात्रा बढ़ जाती है अर्थात् 9.6 आतिरिक्त मांग स्थिति से व लागत स्थिति से संबंधित है। अतः प्रमाँ मात्रा की स्थिति पैदा होती है।

④ Inflationary gap केवल प्रवाह की कारण से संबंधित है - जैसे चालू लागत से व लागत, उपयोग से व व्यय इत्यादि किन्तु पूर्ण रोजगार स्तर पर कीमतों में होने वाली वृद्धि का प्रभाव वस्तुओं के स्टाक पर भी पड़ता है।

Bringing Bridge up or Control of Inflationary gap

Next Page Part - II में है

Sandhya Rai
Dept of Economics